बिक्री कोटा कम रखने से बढ़े चीनी के दाम

कीमतें बढ़ने से निर्यात की रफ्तार भी कम हुई है

[जयश्री भोसले|पुणे]

सरकार के जुलाई के लिए चीनी का बिक्री कोटा सामान्य मासिक बिक्री और इंडस्ट्री की उम्मीदों से कम रखने के कारण चीनी की कीमतों में लगभग 10 पर्सेंट की तेजी आई है।

कीमतें बढ़ने के कारण देश से चीनी के निर्यात की रफ्तार भी कम हुई है क्योंकि मिल मालिक निर्यात में नुकसान उठाने के बजाय घरेलू बाजार में बिक्री करना अधिक पसंद कर रहे हैं।

देश में चीनी की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने जून की शुरुआत से मिलों के लिए चीनी की बिक्री की सीमा तय की थी। देश में चीनी की मासिक खपत 20-21 लाख टन की है। चीनी की सालाना मांग करीब 250 लाख टन है। सरकार ने जुलाई के लिए 16.5 लाख टन का कोटा दिया है। जून में यह 21.5 लाख टन था।

बॉम्बे शुगर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अशोक जैन ने बताया, 'S-30 ग्रेड चीनी की कीमत 29 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर मंगलवार को 32 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। हम 19-20 लाख टन के कोटा की उम्मीद कर रहे थे। कम कोटा से चीनी की कमी जैसी स्थिति बनी है और कीमतों में वृद्धि हुई है।'

चीनी की सालाना मांग करीब 250 लाख टन है। सरकार ने जुलाई के लिए 16.5 लाख टन का कोटा दिया है। जून में यह 21.5 लाख टन था

सरकार ने मिलों के लिए 2017-18 के सीजन में 20 लाख टन चीनी का निर्यात करना भी अनिवार्य किया है। यह सीजन सितंबर 2018 में समाप्त होगा।

निर्यातकों का दावा है कि देश में चीनी की कीमतें बढ़ने के बाद अब मिल मालिक चीनी का निर्यात नहीं करना चाहते। निर्यातक चीनी के निर्यात के लिए लगभग 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत की पेशकश कर रहे हैं। प्रत्येक मिल की चीनी की रिकवरी के पर्सेंटेज के आधार पर 7-8 रुपये की उत्पादक की सब्सिडी को मिलाकर मिलों को निर्यात के लिए 27-28 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत मिल रही है।

महाराष्ट्र में चीनी के व्यापारी अभिजीत घोरपड़े ने आरोप लगाया कि चीनी की बिक्री का कोटा कम करने का फैसला कुछ ताकतवर व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। उन्होंने कह, 'उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अधिक कोटा की मांग की थी जिससे चीनी मिलों को अधिक बिक्री कर गन्ने की बकाया रकम चुकाने में मदद मिल सके। लेकिन इसके बावजूद कोटा कम रखा गया।'

उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई के लिए कोटा जून से 60 पर्सेंट अधिक रखने को कहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने यह मांग नहीं मानी।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की बिक्री का मासिक कोटा हटाने की भी मांग की है क्योंकि अब सरकार ने चीनी के लिए न्यूनतम बिक्री मूल्य तय कर दिया है।